



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, ३ फरवरी, १९९७/ १४ मार्च, १९९८

हिमाचल प्रदेश सरकार

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-२, २७ जनवरी, १९९७

संख्या ई० एक्स० एन०-एफ० (१३) १/९६ (III).—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश जनरल सेल्ज टैक्स ऐक्ट, १९६८ (१९६८ का २४) की धारा ४२ की उप-धारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये “प्रेसिडेंसियस उद्योग” (जिसमें सीमेंट उद्योग सम्मिलित नहीं है) जो कि १-१०-१९९६ को या उसके पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन में आया हो, और आबकारी एवं कराधान विभाग के साथ व्योहारी के रूप में रजिस्ट्रीकृत हुआ हो के द्वारा निर्माण किए गए माल के विक्रय में निम्नलिखित शर्तों के अधीन विक्रय कर से प्रारम्भिक ५ वर्षों की अवधि के लिए छूट प्रदान करता है, अर्थात् :—

- (i) पात्र औद्योगिक इकाई, हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में १२-२-१९९२ को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश सरकार के आबकारी एवं कराधान विभाग की अधिसूचना संख्या १-१२/७३-ई० एण्ड टी०-III तारीख ७-२-१९९२ द्वारा विहित और इसके विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी प्ररूप आर० एम०-II, में एक प्रमाण-पत्र प्रत्येक वर्ष ३० अप्रैल तक समुचित निर्धारण प्राधिकारी के पास दायर करणी।

(ii) यह कि छूट की प्रसुविधा (लाभ) तभी मिलेगा जबकि—

- (क) समस्त विनिर्मित माल का बिक्रय निर्माताओं द्वारा स्वयं किया जाए परन्तु यदि सम्बन्धित औद्योगिक इकाइयों द्वारा हिमाचल प्रदेश में पुनः विक्रय के लिए क्रय किए गए या अर्जित तैयार माल पर छूट नहीं मिलेगी ;
- (ख) उन समस्त औद्योगिक इकाइयों जिसमें आबकारी एवं कराधान विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1-12/73-ई0 एण्ड टी0-III, तारीख 25-9-1992 द्वारा यथा अधिसूचित और 1-10-1992 के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशित और इस विभाग की अधिसूचना संख्या ई0 एक्स0 एन0-एफ0(13) 1/96 (VI) तारीख 27-1-1997 द्वारा यथा संशोधित (सी औद्योगिक ब्लॉक के प्रवर्ग में स्थित इकाइयों और इस अधिसूचना के उप-पैरा (III) में विनिर्दिष्ट इकाइयों से अन्यथा) नकारात्मक सूची में आने वाली इकाइयां भी सम्मिलित हैं; और
- (ग) केवल उन औद्योगिक इकाइयों को जो हिमाचल प्रदेश जनरल सेल्ज टैक्स ऐक्ट, 1968 के समस्त उपबन्धों और तद्धीन बनाए गए नियमों, और जारी अधिसूचनाओं का अनुपालन करें; और

(iii) यह कि छूट की प्रसुविधा (लाभ) किसी भी प्रवर्ग के औद्योगिक ब्लॉक में स्थित निम्नलिखित औद्योगिक इकाइयों को उपलब्ध नहीं होगी :—

- (क) बूरी, आसवनी, फलों पर अनाधारित वाईनरी और बार्टलिंग प्लांट (देसी शराब और भारत में विनिर्मित विदेशी शराब दोनों वाले) ;
- (ख) ईंधन, चारकोल और खैर, रेजिन और सीडार लकड़ी के ठूंड के कच्चे माल पर आधारित उत्पादन ; और
- (ग) पावर इन्टैसिव इकाइयां जहां निवेशों की ऊंची कीमत हो या सशक्त समिति द्वारा यथा निर्धारित ।

2. हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश जनरल सेल्ज टैक्स ऐक्ट, 1968 (1968 का 24) की धारा 42 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 प्रतिशत की दर से विक्रय कर उद्ग्रहित करने और “ए”, “बी” और “सी” औद्योगिक ब्लॉक के प्रवर्ग में स्थित प्रेस्टीजियस उद्योगों (जिसमें प्रेस्टीजियस सीमेंट उद्योग सम्मिलित नहीं है) के लिए इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट पैराग्राफ (1) में प्रारम्भिक अवधि के 5 वर्षों का निशेष करने के पश्चात् क्रमशः सात वर्षों, चार वर्षों, और 2 वर्षों की अवधि के लिए इन द्वारा माल के विनिर्माण और विक्रय के विषय में उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन उद्ग्रह्य विक्रय कर के शेष भाग के संदाय से इस अधिसूचना के उपर्युक्त पैरा में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन छूट भी प्रदान करते हैं ।

स्पष्टीकरण.—(1) इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए पद “औद्योगिक ब्लॉक” और “सशक्त समिति” का वही अर्थ होगा जो कि उन्हें इस विभाग की अधिसूचना संख्या 1-12/73 ई0 एण्ड टी0-III, तारीख 25-9-1992, राजपत्र हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में 1-10-1992 को प्रकाशित अधिसूचना में समनुदेशित किए गए हैं और इस विभाग की अधिसूचना संख्या ई0 एक्स0 एन0-एफ0 (13) 1/96 (VI) तारीख 27-1-1997 द्वारा यथा संशोधित है ।

(2) “प्रेस्टीजियस उद्योग” से कोई नई औद्योगिक इकाई (सीमेंट बनाने वाली इकाई को छोड़ कर) जो कि 1-10-1996 को या बाद में वाणिज्यिक उत्पादन में आया हो और 1-10-1996 को या बाद में “सशक्त समिति” में रजिस्ट्रीकृत हुआ हो, कम से कम 75 करोड़ रुपये का नियत निवेश रखता हो और समस्त श्रेणियों के पदों पर कम से कम 200 व्यक्तियों को

नियमित आधार पर नियोजित करें या अपनी कुल मानव शक्ति का 50 प्रतिशत या जो भी अधिक हो, हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी हों और ऐसी औद्योगिक इकाइयों में से हों जो—

- (i) स्थानीय कच्चे माल पर आधारित हो, या
- (ii) 50 प्रतिशत या अधिक मूल्य परिवर्धन क्रियान्वित करे, या
- (iii) इसके उत्पाद का (देश के बाहर) 50 प्रतिशत या इससे अधिक निर्यात करने का वचनबंध करें; और
- (iv) सशक्त समिति की राय में "प्रेस्टीजियस उद्योग" के रूप में विचार किए जाने के लिए पात्र हों और एक्विटी शेयर का कम से कम 25 प्रतिशत विदेशी सहयोग सहित संयुक्त योजना के रूप में सम्मिलित हो और ऐसी योजना की कम से कम लागत 50 करोड़ रुपये होगी जिसकी ऐसी संयुक्त योजना के वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ के दिन से गणना की जाएगी।

आदेश द्वारा,

एस0 एस0 परमार,
वित्तायुक्त एवम् सचिव।

[Authoritative English Text of this Department Notification No. EXN-F(13)1/96 (iii) dated 27-1-1997 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 27th January, 1997

No. EXN-F(13)1/96(III).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 42 of the Himachal Pradesh General Sales Tax Act, 1968 (Act No. 24 of 1968), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to grant exemption from the payment of sales tax in respect of goods manufactured and sold by the "prestigious industries" (excluding the cement industry) which came into commercial production on or after 1-10-1996 and which are registered as dealer with the Excise and Taxation Department for a initial period of five years, subject to the following conditions :—

- (i) that the eligible industrial unit will file by the 30th April every year with the appropriate Assessing Authority a certificate in Form R.M.II prescribed by the Himachal Pradesh Government Excise and Taxation Department's Notification No.1-12/73 E&T-III, dated 7-2-1992 and published in Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) on 12-2-1992 issued by the authority specified therein;
- (ii) that the benefit of exemption will be available :—
 - (a) when all the goods manufactured are sold by the manufacturers themselves and it shall not be open for finished goods purchased or acquired by concerned industrial units for re-sale in Himachal Pradesh ;
 - (b) to 'all new industrial units' including the industrial units falling in the negative list (other than those located in 'C' category of industrial block and those specified in sub-para (III) of this notification notified vide this Department Notification No.1-12/73-E&T-III, dated 25-9-1992, and published in Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) on 1-10-1992 and as amended vide notification No. EXN-F(13)1/96-(vi) dated 27-1-97; and
 - (c) only to those industrial units which comply with all provisions of the Himachal

Pradesh General Sales Tax Act, 1968, rules framed and the notifications issued thereunder; and

(iii) that the benefit of exemption will not be available to the following industrial units located in any category of industrial block :—

- (a) Breweries, Distilleries, non-fruit based wineries and bottling plants both for Country Liquor and Indian Made Foreign Liquor;
- (b) producing firewood, charcoal and goods based on raw-material of Khair, Resin and Cedar Wood, Stumps; and
- (c) power-intensive units where the cost of power input is high or as may be fixed by the Empowered Committee.

2. The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 42 of the Himachal Pradesh General Sales Tax Act, 1968 (Act No. 24 of 1968) is further pleased to levy sales tax @1% and also to grant exemption from the payment of remaining part of the sales tax leviable under section 6 of the aforesaid Act in respect of goods manufactured and sold by the 'prestigious industries' (excluding cement industry) located in 'A', 'B' and 'C' category of industrial blocks for a period of seven years, four years and two years respectively after exhausting the initial period of exemption for five years, as specified in paragraph (1) of this notification subject to all conditions as specified above in paragraph (1) of this notification.

Explanation.—(1) For the purpose of this Notification the expressions 'industrial block' and 'Empowered Committee' shall have the same meanings as assigned to them in this Department Notification No.1-12/73 -E&T-III, dated 25-9-1992, published in Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) on 1-10-1992 and as amended vide this Department Notification No. EXN-F-(13)1/96 (vi) dated 27-1-1997.

(2) 'prestigious industry' means any new industrial unit (excluding a unit manufacturing cement) which comes into commercial production on or after 1-10-1996 and is registered with the Empowered Committee on or after 1-10-1996 having fixed capital investment of at least Rs. 75 crores and employing on regular basis in all categories of posts at least 200 persons or 50% of employees in its total manpower, whichever is greater, who are bonafide residents of Himachal Pradesh and such industrial unit :—

- (i) is based on local raw materials, or
- (ii) carries out value addition of 50% or more, or
- (iii) undertakes to export (outside the Country) 50% or more of its produce, or
- (iv) deserves to be considered as 'prestigious industry' in the opinion of the Empowered Committee,

and includes a joint venture project with foreign collaboration, with a minimum 25% of equity share capital of foreign collaboration and with a minimum cost of such project to be Rs. 50 crores as computed on the day of commencement of commercial production by such joint venture project.

By order,

S. S. PARMAR,
Financial Commissioner-cum-Secretary.